

‘अगर केरल में जीतना है तो वेणुगोपाल को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर वहाँ भेजो’

कांग्रेस में यह आवाज जोरों से उठ रही है, पर, सवाल यह है कि यह मांग वेणुगोपाल को गौरवान्वित कर रही है या उनकी खिल्ली उड़ा रही है?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जंग का माहौल है, अगर पार्टी को केरल में जीतना है तो के.सी. वेणुगोपाल को केरल भेजो बतौर पीसीसी अध्यक्ष, अन्यथा वाम मोर्चा राज्य में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ सकता है!!

क्या यह चुटकी ली जा रही है, क्योंकि पार्टी के कई गुट चाहते हैं कि वेणुगोपाल, एआईसीसी से और कांग्रेस की सत्ता से बाहर हो जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद को पार्टी का निर्विवाद राजा बना लिया है, उन्हें राहुल गांधी के वीडो के साथ और उनका पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा के.सी. वेणुगोपाल को सौंप दिया है और इससे कांग्रेस के कई नेताओं को भारी नाराजगी है, जो महसूस करते हैं कि वेणुगोपाल अपनी मर्जी से काम करते हैं और पार्टी के हित को ध्यान में नहीं रखते।

- अधिकतर नेतागण वेणुगोपाल को केरल इसलिए भेजना चाहते हैं, जिससे ए.आई.सी.सी. में घुटन कम हो।
- वेणुगोपाल पर राहुल गांधी को इतना “भरोसा” है, कि जब तक वेणुगोपाल की मोहर नहीं लगती ए.आई.सी.सी. में कोई काम नहीं होता।
- अच्छे-अच्छे नेता भी इस कथन की सत्यता से पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं तथा उन्हें वेणुगोपाल के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता है। यहाँ तक कि राहुल के नज़दीकी व विश्वासपात्र अजय माकन भी अब वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम करने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं।
- वेणुगोपाल ने हर राज्य में एक अपना मनपसंद प्रभारी नियुक्त कर रखा है और ये प्रभारी वेणुगोपाल के मन के अनुरूप राज्य में कांग्रेस को चलाते हैं।

कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने के.सी. वेणुगोपाल के आगे समर्पण कर दिया है, और वे उनके आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते

हैं कि राहुल गांधी तक पहुँचने का रास्ता के.सी. वेणुगोपाल के माध्यम से ही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के एक वफादार और करीबी साथी अजय

माकन, जो एआईसीसी के कोषाध्यक्ष हैं, को भी किसी निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने से पहले वेणुगोपाल से मिलना पड़ता है। क्योंकि राहुल ने माकन को कह दिया है कि उन्हें वेणुगोपाल से बात करनी चाहिए।

के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन ने इंदिरा भवन से काम करने का निर्णय लिया है, बजाय 24 अकबर रोड के।

क्यों, जबकि कोई कार्यक्रम इंदिरा भवन तक पहुँच ही सकता और किसी नेता से मिल भी नहीं सकता? इसका उत्तर एक पुराने कांग्रेस विश्लेषक से मिला, जो कहते हैं कि माकन व वेणुगोपाल चाहते हैं कि सार्वजनिक संपर्क, जितना संभव हो सके, कम रखा जाए।

और बाकी महासचिव और राज्य प्रभारी का क्या, वे पार्टी कार्यालय क्यों नहीं आते और वहाँ से काम क्यों नहीं करते?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘महबूबा ने भी एक महिला का बुर्का उतरवाया था’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, “लोग शायद इस बात को भूल गये हों कि महबूबा मुफ्ती ने एक वैध मतदाता का बुर्का एक मतदान केन्द्र के अंदर हटवाया था। यह उसी मानसिकता की निरंतरता है।” उमर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब विवाद पर आलोचना करने वाले पहले नेताओं में से थे, ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी महबूबा पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक साम्प्रदायिक पार्टी के सहयोगी के रूप

- जम्मू कश्मीर के मु.मंत्री उमर अब्दुल्लाह ने याद दिलाया कि मतदान केन्द्र में महबूबा मुफ्ती ने वोट डालने आई एक महिला का बुर्का उतरवाया था।

में एक महिला डॉक्टर का बुर्का हटाकर, “अपना असली रंग दिखा रहे हैं।” अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि यह ट्रेंड महबूबा ने ही शुरू किया था। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2004 के चुनावों के दौरान, मुफ्ती ने एक महिला का बुर्का उड़ाया था। जब इसके लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने कहा था कि वह मतदाता की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि बुर्के का इस्तेमाल अक्सर झूठे वोट डालने के लिए किया जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नारी सशस्त्रीकरण का नारा अति प्रचलित है आजकल राजनीति में’

प्रशांत किशोर ने डेढ़ घंटे की मुलाकात में प्रियंका गांधी को यह “नेक” सलाह दी कि उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस की राजनीति में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से हाल ही में हुई मुलाकात दरअसल सिर्फ इतना ही दर्शाती है कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक कांग्रेस के साथ संभावना एवं अवसर की एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं।

नई दिल्ली में दोनों नेताओं की डेढ़ घंटे की इस मीटिंग के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई कि किशोर ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदले जन सुराज पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जेएसपी के सूत्रों ने ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीके खुद को इस तरह कम करके नहीं आँकते।

हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में कांग्रेस और जन सुराज पार्टी, दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वह सिर्फ छह पर जीत हासिल कर सकी, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जबा हो गई। संभवतः दो पराजित दलों

- प्रशांत किशोर का मानना है कि राजनीति में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं. अतः कुछ समय बाद, कालांतर में कांग्रेस की स्थिति में सुधार अवश्य होगा और वे कांग्रेस के लिए अवैतनिक (फ्री) सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं।

- जैसा कि विदित ही है, बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों, कांग्रेस व प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, की बहुत खराब हालत हुई थी। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा केवल छः सीटों पर ही जीत पाई तथा जन सुराज पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा सभी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी।

- प्रशांत किशोर सदा राहुल से ज्यादा प्रियंका के नज़दीक थे तथा 2017 के यू.पी. के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तैयार करते समय, उन्होंने प्रियंका गांधी को मु.मंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की राय दी थी।

- प्रियंका भी काफी इच्छुक थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस जाँइन कर लें।
- अब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए एक खिड़की खोल ली है।

का विलय बिहार में या कहीं भी कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बोतलबंद पानी की अशुद्धता की याचिका शहर केन्द्रित सोच का प्रतीक’

सी जे आई ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए “लगज़री” मुकदमा और अमीरों की चॉंचलेबाजी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को नकारते हुए कहा कि भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बुनियादी पेयजल तक से वंचित है। कोर्ट ने इस याचिका को “लगज़री मुकदमा” करार देते हुए, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार तक करने से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच, सारंग वामन यादवड़कर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि देश में बिकने वाला पैकेज्ड पानी विकसित

- याचिकाकर्ता की वकील अनिता शेनॉय ने कहा कि यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और उपभोक्ता को स्वच्छ व शुद्ध बोतलबंद पानी मिलना चाहिए और इसमें डबल्यू एच ओ के मानकों का पालन होना चाहिए
- चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, जब गांधी जी भारत लौटे थे, तो गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में गए थे, याचिकाकर्ता से कहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाए और देखे कि लोग पीने का पानी पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, तब उसे समझ आएगा, असली भारत की तकलीफ क्या है।

देशों के मानकों, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक शामिल है, के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड पानी के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स

अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ एस एस ए आई) के तहत बोतलबंद पानी के नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आदेश देने की मांग की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट में लोक अदालत आज

जयपुर, 18 दिसंबर। राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब लोक अदालत की शुरुआत दोपहर 3.30 बजे से होगी। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इसी तरह

- राजीनामा करने के लिए जयपुर व जोधपुर में तीन-तीन बेंच बनाई गई हैं।

जोधपुर में जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी इसकी शुरुआत करेंगे।

जयपुर पीठ में मुकदमों के आपसी राजीनामे के जरिये निपटारे के लिए तीन बेंच बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता मौजूदा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर, जस्टिस संदीप तनेजा और जस्टिस बिपिन गुप्ता करेंगे। वहीं, इनमें सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गुप्ता, महेंद्र शाह और अजय कुमार बाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीति आयोग के पूर्व कर्ताधर्ता अमिताभ कांत सरकार से इतने रुष्ट क्यों हैं?

अमिताभ कांत की पीड़ा यह है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नाम पर नये-नये मापदंड लाए जा रहे हैं, एम.एस.एम.ई. सैक्टर पर, जिससे भारत में निर्मित माल, विश्व की सप्लाई शृखंला का हिस्सा नहीं बन पा रहा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के तेजी से बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) सिस्टम की अब तक की सबसे तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जिसे आधिकारिक तौर पर स्टैंडर्ड और सुरक्षा अभ्यास के रूप में पेश किया जा रहा है, वह असल में संरक्षणवाद का सीधा हथियार बन गया है, जो प्रतिस्पर्धा, रोजगार और एमएसएमई को नुकसान पहुँचा रहा है।

‘पॉडकास्ट “यो” में मोनिका हलान से बातचीत करते हुए कांत ने कहा कि क्यूसीओ का व्यापक और बेतहाशा विस्तार, जो अब 760 से अधिक उत्पादों और क्षेत्रों को कवर करता है, “संरक्षणवाद का सबसे खराब रूप” है।

- क्वालिटी कंट्रोल के यह मापदंड 760 प्रोडक्ट्स व सैक्टर पर लगाये गए हैं तथा ज्यादा वेदना का विषय यह है कि ये मापदंड “इनपुट” (निर्माण) में काम आने वाले सामान पर लागू किए गये हैं। मापदंडों की पालना से भारतीय सामान महंगा होता जा रहा है तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देश अपना सामान भारत की तुलना में सस्ता बेच रहे हैं और भारत अपना निर्यात बढ़ाने का सुअवसर खोता जा रहा है।

खासतौर पर इसलिए, क्योंकि इनमें से कई आदेश अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं, बल्कि कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और पुर्जों पर लगाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यहीं पर भारत खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

कांत के मुताबिक, इनपुट्स (उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल) पर बाधाएँ बढ़ाकर क्यूसीओ गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं की तरह

काम करते हैं। इससे आयात सीमित होता है और घरेलू निर्माताओं के लिए लागत बढ़ जाती है। कांत ने कहा, इसका सबसे ज्यादा बोझ एमएसएमई पर पड़ता है, जिनके पास न तो इतनी बड़ी क्षमता होती है और न ही सौदेबाजी की ताकत कि वे ऊँची इनपुट कीमतों या जटिल अनुपालन नियमों को आसानी से झेल सकें। नतीजा यह होता है कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक वैल्यू चेन में कम

प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं, जिससे सरकार द्वारा समर्थित मैनुफैक्चरिंग और निर्यात महत्वाकांक्षाएँ ही कमजोर होती हैं।

कांत ने कहा कि समस्या अब सीमित या लक्षित हस्तक्षेप तक नहीं रही है, बल्कि यह बेकाबू विस्तार का रूप ले चुकी है। बोते एक साल में ही सैकड़ों नए क्यूसीओ जारी किए गए, वह भी अक्सर बिना पर्याप्त परामर्श के। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट लागत बढ़ी है, मुनाफे के मार्जिन सिमटे हैं और कंपनियाँ वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जुड़ने से हतोत्साहित हुई हैं। कुछ खास उत्पादों के लिए सीमित क्यूसीओ को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन मौजूदा “बेलगाम” फैलाव, उनके अनुसार, कच्चे माल और पुर्जों को बेवजह महंगा बनाकर भारत की विकास कहानी को नुकसान पहुँचा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक के ईडी केस के आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 18 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने ये आदेश

- हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण निचली अदालत में आरोप तय नहीं हो पाए।

आरोपी राजाराम उर्फ इरम की द्वितीय जमानत याचिका खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अभियोजन साक्ष्य छह माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण आरोप तय नहीं हो सका वहीं, अन्य सह आरोपियों ने भी दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि उपलब्ध कराने के लिए कई आवेदन दायर किए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन पर विधिवत निर्णय पारित किया गया। ऐसे में मुकदमे में देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एसएलपी खारिज करते हुए निचली

विचार बिन्दु

सत्याग्रह बल प्रयोग के विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। –महात्मा गांधी

महाअभियोग के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरूद्ध न केवल अलोकतांत्रिक है, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है

देश के 56 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें संसद के उन सदस्यों को विद्बुो करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरूद्ध महाअभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है। संसद के अध्यक्ष को प्रेषित किया है उसकी प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि यह कार्य संविधान के प्रावधानों की गरिमा उद्देशिका में वर्णित मूल भवना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है।

अपने पत्र में 50 पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिये हैं कि कुछ सांसदों और एडवोकेट्स न्यायालय (न्यायाधीशों) को दबाव में लाना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिये कि वे लोग जस्टिस महोदय की राजनीतिक अथवा Ideological विचार धारा से सहमत नहीं हैं। यह सोच न्यायाधीश स्वतंत्रता के विरूद्ध है व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।

यह घटना क्रम उस समय हुआ, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पिटीशनर को पिटीशन पर जो अपने को Right Wing Activist मानता है, जस्टिस स्वामीनाथन ने, सुनवाई के बाद यह निर्देशन राज्य सरकार को दिया कि पवित्र दीपक पहाड़ी शिखर पर प्रज्वलित किया जा सके इसकी व्यवस्था हो ताकि कोई व्यवधान न हो। राज्य के अधिकारियों का कथन था कि दीप मंडप के सामने दीपक जलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। मस्जिद और दीप दोनों पहाड़ी की चोटी पर हैं बीच में रिक्त स्थान है। ऐसा भी है कि कोर्ट के निर्णय है जहां दीप मंडप पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा का जिक्र है। लेखक का इस प्रसंग के कानूनी गुणदोष पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। प्रश्न इतना है कि जब जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है तो फिर क्या मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध इस आदेश को महाअभियोग की कार्यवाही के द्वारा बिना निरस्त किये जस्टिस महाअभियोग की सजा में नौकरी से निकाला जा सकता? 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रकार नौकरी ने निकालने की कार्यवाही करना सर्वथा अवैध, अन्धकृत और विवेकहीन है। नि:सन्देह इस प्रकार की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों को Brow Beat करना ही कहा जावेगा। लोकतंत्र में न्यायाधीश को निर्भीक व स्वतंत्र विचार धारा का होकर संविधान व लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार एक सबल रक्षक के रूप में काम करना होता है। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में विचार रखते हुये कहा है महाअभियोग के प्रतिवेदन में कोई भी संगत आधार प्रतिक्षित नहीं होते, क्योंकि महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिये। लोकतंत्र में न्यायालयों को स्वतंत्र, किसी बाहरी शक्ति के दबाव से दूर ही रहना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही रूला ऑफ लॉ के लिये गम्भीर खतरा है। महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण है यह कार्यवाही तो न्यापालिका की गरिमा को बनाये रखने के हेतु ही की जाना अपेक्षित है। संविधान ने अपनी उद्देशिका में स्पष्ट घोषणा की है, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमों और आत्मार्पित करते हैं।

पूर्व न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये सब ही यशस्वी न्यायाधीश रहे हैं, अतः इन सबसे जब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में उपरोक्त संदर्भ में कोई बात कही है तो उसका महत्व हमें समझाना होगा, यह विषय महाअभियोग लाने का तो नहीं हो सकता है।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी। उसके साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कुछ गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति की थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुये माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य केस में सुनवाई के समय कहा था कि वे टफ आदमी हैं कोई ऐसा नहीं समझे कि न्यायपालिका ऐसी क्रियाओं पर दबाव में आ जायेगी। जस्टिस बागची ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि "जजों द्वारा सवाल पूछने से रोकने का यह एक संगठित प्रयास है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश ने रोहिंन्या घुसपैठियों का रैड कारनेट (लाल कालीन) निष्ठाकर स्वागत करें"।

कई बार टिप्पणी के द्वारा न्यायाधीशगण समस्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाना चाहिये, किन्तु ऐसी टिप्पणी को जज ही पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इन सब परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। इसे सावधानी से रोकना और गम्भीरता से विरोध करना अतिआवश्यक है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा सोशल मिडिया को नियंत्रित करने के समाचार के विषय में कहा कि ऐसे कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सोशल मिडिया पर यह टिप्पणी की कि सोशल मिडिया जब संदर्भ हटाकर ट्रोलिंग की जाने प्रवृति को अपनाता है, उसकी अन्देखी भी नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र की मजबूती इस पर निर्भर है वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं है जैन धर्म के धर्मावलंबियों की एक प्रार्थना है, "रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, या कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग मेरा कभी न पथ डिगने पाये"।

इसका अर्थ है नयायाधीश निष्पक्ष हो विषय का ज्ञाता हो, केस की, जिसका उसे निर्णय करना है, उसके तथ्यों की पकड़ हो, जिसकी IntegrityMebkeâe से परे हो। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था:-

‘धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्त्वियो मा नो धर्मो हतोऽवधीतु।' "Dharma protects those who protect it. Those who destroy Dharma gets destroyed as a consequence thereof."

क्या जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत हो। फिर क्या उनके विरूद्ध महाअभियोग की असाधरण कार्यवाही की जावे?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, शुल योग दिन 3:47 तक, चतुष्पद करण सायं 6:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:51 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक

राजस्थान में बिना महाविद्यालय और अध्यापकों के कृषि उच्च शिक्षा - एक प्रस्तावित मॉडल



वीर बहादुर सिंह

विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर को देखते हुए अब प्रतीत हो रहा है कि स्नातक कृषि शिक्षा में भी कुछ नवीन आयाम खुलने चाहिए अथवा शिक्षा प्रदान करने की कक्षा कक्ष की प्रणाली में कुछ परिवर्तन घटित हों। ऐसा इसलिए कि विषय वस्तु भार अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में यदि अपरिमित संसाधन और विषय सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में होता रहे तो छात्र के लिए उसे आत्मसात करने के लिए समय कम पड़ सकता है, और अध्यापक के लिए कालांश की संख्या में बढ़ोतरी भी जरूरी हो जाती है। हमें याद है आरम्भ में स्नातक केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम ही था, बहुती विषय सामग्री ने सेमेस्टर पद्धति में चार सेमेस्टर, फिर छः और अब आठ सेमेस्टर तक पहुंचा दिया है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों को राहत स्वरूप कुछ परिवर्तन जरूरी है। पाठक इस लेख के लेखक को कोसें नहीं, लेख में वर्णित व्यवस्था लेखक को राजस्थान में वर्षों कार्य के दौरान प्राप्त वृहत अनुभवों पर बलवती होती धारणा पर आधारित है। कृषि उच्च शिक्षा की एक परिवर्तित प्रणाली, जिसमें

महाविद्यालय बनाने और अध्यापकों को नियुक्ति से निजात मिलेगी। लेखक ने इस प्रणाली को बिना अन्य से विमर्च और सम्बाद किये स्वयं ही रूप देने का प्रयास किया है।

इस प्रणाली को उत्पन्न करने और मूर्तरूप देने में प्रदेश सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों पर सदैव आर्थिक दृष्टि से आंखू बहाने का दृश्य मुख्य कारक रहा। कृषि शिक्षा को राजस्थान सरकार फिजूल का उपक्रम मानती रही है और इसीलिये कृषि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार सदैव उदासीन, गैरजम्मेदार और कभी कभी विरोधी भी रही है। मेरी समझ से इसका मुख्य कारण योजना नियोजकों को कृषि के असंख्य पहलुओं पर उनकी सभी स्तरों पर अनिभिज्ञता और नासमझी ही है। प्रदेश के बहुत से अधिकारिओं को अभी तक ज्ञात होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय भी एक विशेष शाखा के तौर पर पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र विज्ञान, शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारिओं के पसोंने छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गईं। जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

ये है जब सरकार ने नियुक्ति प्रणाली को शुरू ही नहीं क्या तो फिर गति किसको और फिर उनका निर्देश किसको है जबकि वे खुद ही सर्वसर्वा हैं। नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के ही पास है। जनता को मूर्ख बनाने और एक सफूंगा छोड़ने के अलावा ऐसा निर्देश कोई मायने नहीं रखता। पाठक इस बात पर चिंतन करें कि कक्षाओं में पढ़ाई कैसे हो रही है जब उचित अध्यापक ही नहीं हैं और पढ़ाई की निगरानी के लिए महाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा अधिष्ठाता भी महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय का नहीं है। न, पहली, क्योंकि बिना उचित विषय विशेषज्ञ के कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? परीक्षा भी हो रही है और छात्र उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, है न आश्चर्य?

इसका कारण, कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स नेट पर उपलब्ध करा रखे हैं। छात्र उन्हें ही अपने स्मार्ट फ़ोन में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सैद्धांतिक पढ़ने के लिए कक्षा और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार ध्योरी क्लासेज की ग्लुथी तो सुलझती प्रतीत लग रही है फिर भी इन नोट्स में वर्णित विषय सामग्री को और अधिक ग्राह्य तथा विकसित किया जा सकता है। अब दूसरी यह कि प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होता है? कृषि में ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रैक्टिकल खेतों, फार्म, नदियों, तालाबों, बनों, बाधों, और फसलें उगे हुए किसानों के खेतों पर कराये जा सकते हैं। अभी तो करोड़ों रुपये के महंगे प्रयोशाला उपकरण वर्षों से भूल चाट रहे हैं और संभवतः अनेक जो खाखर बेकार भी हो चुके हों? खोजबन करने पर मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल तो विषय का टीचर नहीं

होते हुए कराये ही नहीं जा रहे हैं। प्रयोशाला सहायक ही नहीं है, कराये का टीचर हो लैब में जाकर कतिपय उपकरण दिखा कुछ बता देता है अधिक बताने के लिए उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसे तो कालांश किसी प्रकार पूरा करना है। वह हो जाता है आखिर में उसका पारश्रमिक बना कर अदा कर दिया जाता है। लेखक चौंक इस विषय पर अधिक गंभीर था तो अनेक व्यक्तित्वों से पूछ कर वांछित जानकारी जुटाना संभव हो सका। प्रदेश सरकार को कृषि अनुसन्धान परिषदों वाले किसी भी चाहिए कि छात्रों को प्रत्येक विषय के विस्तृत विवरण नेट पर उपलब्ध अतः कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जरूरत नहीं। भारी वेतन पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी।

अब केवल प्रैक्टिकल करने या कराने की बात शेष रहती है। मेरे पास विकल्प है लेकिन उसके लिए विचार-विमर्श सरकार के स्तर पर भी जरूरी है। सरकार के प्रशासन वर्ग को मैं सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और विवेकशील मानता हूँ इसलिए इस विषय पर आगे मंथन वहां से भी अपेक्षित है।

यदि यह प्रणाली कारगर हो गई तो प्रदेश सरकार के लिए तो वरदान साबित होगी और छात्र का समय बचेगा। रिक्त पदों और उन्हें भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से घन की अपार बचत होगी। सरकार की आर्थिक शक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। जय कृषि जय किसान जय भारता

–प्रो.वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता खेरी व डेरा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. विद्यालय, उदयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा बजट प्रस्ताव 2026-27



अशोक कुमार

राजस्थान के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश अनिवार्य है। बजट प्रस्तावों को केवल व्यय के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजट आवंटन राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तरीय प्रणाली में बदल सकता है।

राजस्थान की उच्च शिक्षा को संवराने में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने हेतु प्रदेश के ये उच्च शिक्षण संस्थान आधारस्तंभ हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान को लेकर अक्सर असमंजस और देरी की स्थिति बनी रहती है। अतः आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के लिए एक स्थायी पेंशन कॉर्पस फंड का प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारियों को नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। यदि विश्वविद्यालयों में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का अपाव रहा, तो प्रदेश के मेधावी युवा अध्यापन के बजाय और सेवाओं की ओर पलायन करीगे, जिससे अंततः राजस्थान की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।आगामी बजट 2026-27 में राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट बजट आवंटन की घोषणा होनी चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संकाय विकास : उच्च विद्यालयी गुणवत्ता सीधे शिक्षकों की क्षमता और संसाधनों से जुड़ी होती है।

1. संकाय की भर्ती और प्रशिक्षण: शिक्षकों की स्थायी भर्ती: विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र: सभी विश्वविद्यालयों में एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए फंडा। ये केंद्र एनहपी 2020 के अनुसार मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण विधियों और शोध नैतिकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण देंगे। शोध प्रस्ताहनों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ़रेंस में भाग लेने और उच्च गुणवत्ता के पीयर-रिव्यूड जर्नलों में प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन राशि

2. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार:

कौशल-आधारित शिक्षा: कौशल विकास और इंटरशिप को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बजट। इसके लिए स्थायी उद्योगों और एमएसएमइएस के साथ साझेदारी विकसित करने हेतु फंड।

अद्यतन प्रयोगशालाएँ: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने हेतु एक आधुनिकीकरण कोष।

3. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल पहुँच का विस्तार: सभी सरकारी कॉलेजों को हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई से लैस करने के लिए डिजिटल पहुँच मिशन।

ई-संसाधन सब्सक्रिप्शन: सभी छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों (जैसे- स्कोपस) की सदस्यता लेने हेतु केंद्रीय फंडिंग।

स्मार्ट क्लासरूम: 75 प्रतिशत से अधिक कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम (प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड) में बदलने के लिए विशेष परियोजना।

4. भौतिक बुनियादी ढाँचा: कॉलेज भवन और छात्रावास: दूरदराज के क्षेत्रों और छात्राओं के लिए नए छात्रावासों के निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा बजट।

विश्वविद्यालय शोध उपकरण: उच्च-स्तरीय शोध उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर आदि खरीदने के लिए एक शोध उपकरण खरीद निधि।

तीसरा- पहुँच, समानता और समावेशन : राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए वंचित समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

1. छात्राओं के लिए विशेष

योजनाएँ: “उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना”:
ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए नकद प्रोत्साहन या ट्यूशनिय फीस में पूर्ण छूट।
सुरक्षित परिवहन: छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाने के लिए सुरक्षित और सब्सिडीयुक्त परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बजट।
2. वंचित समूहों के लिए समर्थन: विशेष कॉमिंग: एएससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- एनईट, यूपीएससी, लायपीएससी) की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित करने और चलाने के लिए फंड।
डिव्यांगन सहायता: एनहपी 2020 के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा-मुक्त परिसर, विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अलग कोष।
चौथा- अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों को ज्ञान सृजन के केंद्र में बदलना।
पाँचवा- शासन और जवाबदेही संस्थागत प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
डेटा प्रबंधन प्रणाली: समय पर और सटीक डेटा संग्रह के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने हेतु बजट। यह एआईएसएलएच रिपोर्ट में देरी जैसी समस्याओं से बचने में मदद करेगा।
संस्थागत स्वायत्तता प्रोत्साहन: अच्छा प्रदर्शन करने वाले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन वित्तीय लेखापरीक्षा: आवंटित बजट के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित वित्तीय और शैक्षणिक लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था। विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में किया गया निवेश राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कुंजी है।
विज्ञान और एआइ तकनीक के लिए बजट प्रस्ताव
इन प्रस्तावों को तीन प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया जा सकता है: बुनियादी ढाँचा, मानव पूंजी , और अनुसंधान एवं नवाचार।
प्रथम- बुनियादी ढाँचा और डिजिटल क्षमता निर्माण

1. उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएँ:
एआइ सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर: राज्य के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों (जैसे- आइआईटी, एनआईटी, या प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज) में एक या दो उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए फंड।
मांग: जीपीयू सर्वर, शीतलन प्रणाली, और इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट।
2. अटल टिकरिंग लैब और एसीटीएम लैब का विस्तार:
उच्च शिक्षा में अटल लैब: स्कूली शिक्षा में सफलतापूर्वक लागू एटीएल मॉडल को उच्च शिक्षण संस्थानों (विशेषकर पॉलिटेक्निक और छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजों) में एडवांस्ड एसीटीएम लैब के रूप में विस्तारित करने हेतु बजट।
मोबाइल विज्ञान वैन: ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुसज्जित मोबाइल विज्ञान और एआइ लैब वैन की खरीद और संचालन के लिए फंड।
द्वितीय- मानव पूंजी और कौशल विकास और विज्ञान के लिए कुशल कार्य बल तैयार करना
1. एआइ उत्कृष्टता केंद्र: राज्य एआइ केंद्र: कम से कम चार क्षेत्रीय एआइ उत्कृष्टता केंद्र (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) स्थापित करने के लिए पर्याप्त आवंटन, जैसा कि केंद्र सरकार के इश्टया एआइ मिशन में भी प्रस्तावित है (जिसके लिए 10,372 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं)।
फोकस क्षेत्र: इन केंद्रों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष क्षेत्रों (जैसे एग्री-एआइ, हेल्थ-एआइ, गवर्नेंस-एआइ) पर केंद्रित होना चाहिए।
2. संकाय अपस्कीलिंग और भर्ती:
एआइ संकाय फैलोशिप: इंजीनियरिंग और विज्ञान कॉलेजों के शिक्षकों को एआइ/एमएलए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एआइ संकाय फैलोशिप कार्यक्रम शुरू करने हेतु बजट।
विषय-विशेषज्ञों की भर्ती: एआइ, डेटा साइंस, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग विशेषज्ञों को अल्पाकालिक या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए आकर्षक वेतन पैकेज

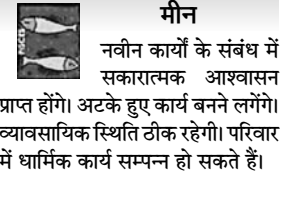
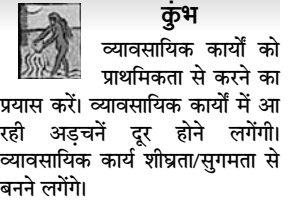
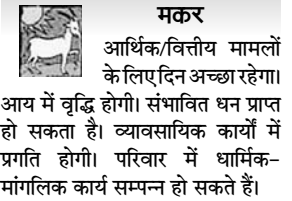
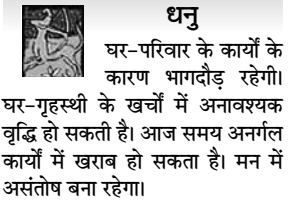
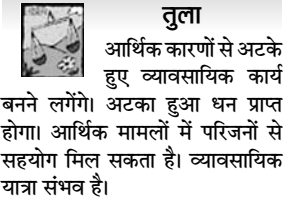
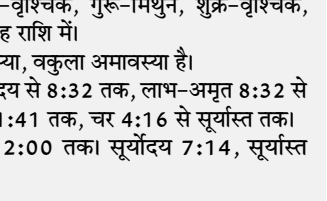
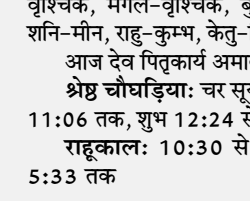
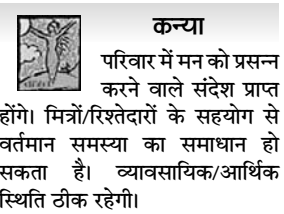
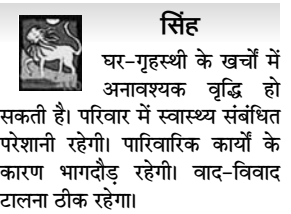
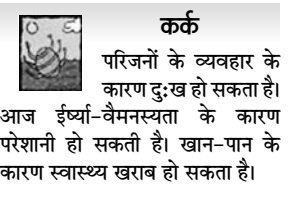
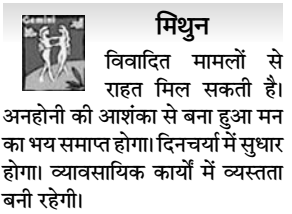
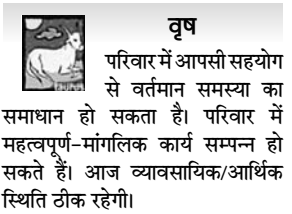


मेघ
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ-मांगलिक कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिजनों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

तुला
आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिजनों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।



पर्यावरण संरक्षण हमारी देश और प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा : भजनलाल शर्मा

हमारे प्रदेश में ‘खेजड़ली का बलिदान’ पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से आवाहन किया कि पर्यावरण संरक्षण हमारी देश और प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम नदियों, पर्वतों, वृक्षों, धरती और सूर्य को पूजते हैं, क्योंकि जीवन की निरंतरता प्रकृति के संरक्षण पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में ‘खेजड़ली का बलिदान’ पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आमजन को आवाहन किया कि, पर्यावरण संरक्षण का व्यक्तिगत संकल्प लेते हुए प्रदेश को विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बनाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिले। शर्मा गुरुवार को जयपुर में आयोजित हरियाली राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से परंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशयों की स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को हरियाली राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में ‘मेरी लाइफ़-सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर’ का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे।

गया है। वहीं, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए 14 हजार से अधिक ग्रांड वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करवाया गया है। प्रधानमंत्री नेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत दो वर्ष में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लेकर आई है। प्रदेश में ई-

वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अधिकृत इकाइयां संचालित की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन-जागरूकता और रिवर्स वॉर्डिंग मशीनों के माध्यम से प्लास्टिक संग्रह को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हम प्रदेश को ग्रीन इनेवेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के

क्षेत्र में राजस्थान तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा प्रदेश 22 हजार 860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2 हजार 272 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सौर ऊर्जा शक्ति का ही परिणाम है कि आज राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन के समय में ही बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे कोयला आधारित बिजली

उत्पादन पर निर्भरता घट रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में बिजली और पानी की उपलब्धता और महिला, युवा, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए एक रोडमैप बनाया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम-कमला-अम्बा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मेरी लाइफ़-सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर’ का विमोचन किया। कॉन्क्लेव में राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों को लेकर लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता और सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल सहित बड़ी संख्या में पर्यावरणविद, विशेषज्ञ एवं उद्योगजगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

देवनानी से हरियाणा के पूर्व मंत्री धनखड की मुलाकात

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरुवार को राजकीय आवास पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने मित्राचार भेंट की। मुलाकात के दौरान देवनानी ने धनखड़ का पारंपरिक रूप से दुपट्टा पहनकर स्वागत किया तथा उन्हें राजस्थान विधानसभा का स्मृति-चिह्न एवं पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर भेंट कर सम्मानित किया। दोनों ने समसामयिक राजनीतिक विषयों, लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं तथा राष्ट्र निर्माण में विधायिका की भूमिका पर चर्चा की। राजस्थान

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से यहां विधान सभा में संस्कृति चिल्ड्रन्स एकेडमी के छात्र-छात्राओं ने मुलाकात की। देवनानी ने बच्चों से कहा कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो और निरन्तर आगे बढ़ते रहो। देवनानी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछा। छात्र-छात्राओं ने राजस्थान विधान सभा सभा का राजनैतिक आख्यान संग्रहालय भवन और सदन देखा। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को संस्कृति चिल्ड्रन्स एकेडमी के बच्चों ने अपने हाथों से बनाये उपहार भेंट किये।

झुन्झुनू से चिड़ावा-पचेरी हरियाणा बॉर्डर तक फोरलेन सड़क बनेगी

जयपुर (कासं)। झुन्झुनू-चिड़ावा-सिंचाना-पचेरी (हरियाणा बॉर्डर सीमा) तक 4 लेन सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 78.180 कि.मी. फोरलेन सड़क (एनएच 11)निर्माण के लिए 2202.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ।

इस परियोजना में झुन्झुनू बीड, बगड, खुडाना, सिंचाना, पचेरी कलां आदि में 4 लेन बाईपास सड़क निर्माण कार्य एवं चिड़ावा में पिलानी सड़क से लाखू तिराहा एवं लाखू तिराहा से ओजड़ तिराहा तक 4 लेन रिग रोड का निर्माण करवाया जायेगा। इस परियोजना में बाईपास सड़क की कुल लम्बाई 41.660 कि.मी. तथा एग्रीजस्टिंग रोड की कुल लम्बाई

- 2203 करोड़ की लागत से 78 कि.मी. हाईवे बनेगा फोरलेन, प्रोजेक्ट में 42 ब्रिज बनेंगे
- प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा और गति मिलेगी : उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी

36.520 किमी में 4 लेन सड़क बनायी जायेगी। उक्त परियोजना में कुल 42 ब्रिज बनाये जाएंगे। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन हाइवे के निर्माण से द्रुत एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे

क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास को नई दिशा एवं गति मिलेगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की उपजों की बड़े बाजारों तक पहुँच आसान होगी जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा है की मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं प्रदेश में मजबूत आधारभूत ढाँचा स्थापित किया जा रहा है , जो प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सुनियोजित शहरी विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयुक्त आनंदी ने बताया कि प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन के साथ स्थित पांच प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डवलपमेंट कॉरिडोर घोषित किया है।इनमें वीर तेजाजी सर्कल से पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन (1.4 कि.मी.), पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन से भारत आश्रम मार्ग जंक्शन (1.5 कि.मी.), भारत आश्रम मार्ग जंक्शन से जनपथ मार्ग जंक्शन (1.1 कि.मी.), जनपथ मार्ग जंक्शन से ईप्सआई रोड जंक्शन (1.6 कि.मी.) और ईप्सआई रोड जंक्शन से टॉक रोड जंक्शन (1.3 कि.मी.) को शामिल किया गया है।

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और सुनियोजित शहरी विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। आयुक्त आनंदी ने बताया कि प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन के साथ स्थित पांच प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट-ओरिएंटेड डवलपमेंट कॉरिडोर घोषित किया है।इनमें वीर तेजाजी सर्कल से पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन (1.4 कि.मी.), पंडित टी.एन. मिश्रा मार्ग जंक्शन से भारत आश्रम मार्ग जंक्शन (1.5 कि.मी.), भारत आश्रम मार्ग जंक्शन से जनपथ मार्ग जंक्शन (1.1 कि.मी.), जनपथ मार्ग जंक्शन से ईप्सआई रोड जंक्शन (1.6 कि.मी.) और ईप्सआई रोड जंक्शन से टॉक रोड जंक्शन (1.3 कि.मी.) को शामिल किया गया है।

जयपुर (कासं)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर झोटवाड़ा के ग्राम नांगल जैसा बोहरा में मेरी पहल संस्था एनजीओ के परिसर में अवैध तौर पर बंधक बनाए गए 18 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुक्त कराया गया। इनमें 11 महिलाएं व 7 पुरुष शामिल थे। वहीं संस्था संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद महिलाओं और पुरुषों को उनके घर भेजा गया। वहीं इनमें से कुछ महिलाओं को महिला सदन में रखा गया है और उनके परिवजनों से संपर्क किया जा रहा है।

कार्रवाई में पता चला कि एनजीओ संस्था के परिसर में संचालक ने खुद को भिक्षुक पुनर्वास केंद्र संचालन करने वाला बताया, लेकिन वहां जो कौशल विकास या पुनर्वास कार्य नहीं किया जा रहा था। रेस्क्यू अभियान की कार्रवाई हाईकोर्ट के एग्रेटोर सीजे व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव

160 देशों के 10 लाख अभ्यासी एक साथ करेंगे ध्यान

जयपुर (कासं)। विश्व ध्यान दिवस पर 21 दिसंबर को हार्टफुलनेस मूवमेंट द्वारा शांति, सद्भाव और आंतरिक संतुलन के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक लाइव मेडिटेशन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र का नेतृत्व हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक पूज्य दाजी कमलेश डी पटेल करेंगे। यह लाइव ध्यान सत्र रात 8 बजे प्रारंभ होगा और 'एक विश्व, एक हृदय' के प्रेरक संदेश के साथ पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोएगा।

कार्यक्रम के राज्य समन्वयक विकास मोधे ने बताया कि इस वैश्विक आयोजन में 160 देशों के 10 लाख से अधिक अभ्यासी ऑनलाइन माध्यम से एक साथ ध्यान अभ्यास करेंगे। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर सहित सभी जिलों के हार्टफुलनेस अभ्यासी और साधक भी अपने-अपने स्थानों से इस सामूहिक ध्यान में सहभागिता करेंगे। राज्य के अनेक केंद्रों पर सामूहिक रूप से स्क्रीन के माध्यम से जुड़ने की भी तैयारियां की जा रही हैं। हार्टफुलनेस संगठन द्वारा आयोजित यह सत्र यू टचयू लू लाइव सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।

1993 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के अभियुक्तों की समय पूर्व रिहाई से हाईकोर्ट का इनकार

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1993 में मुंबई सहित छह राज्यों में हुए सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्तों को समय पूर्व रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अशफाक खान, एफआर सूफी, एआर अंसारी, मोहम्मद एजाज अकबर, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद शमसुद्दीन और मोहम्मद अफाक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि अभियुक्त टाडा के तहत अपराध में आजीवन कारावास की सजा के दोषी हैं। ऐसे में उन्हें समय से पूर्व रिहा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत हाईकोर्ट अपीलीय अदालत की तरह तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन कर दखल नहीं दे सकता, जब तक की प्रशासनिक

- मुंबई सहित छह राज्यों में वर्ष 1993 में हुआ था सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट

निर्णय मनमाना और कानून के विपरीत ना हो। खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियां अत्यंत जघन्य अपराध हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध में दोषी अभियुक्तों की रिहाई ना केवल समाज के लिए खतरा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करेगा।

याचिकाओं में कहा गया कि दिसंबर, 1993 में हुए सीरियल ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में उन्हें दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष टाडा कोर्ट ने 28 फरवरी, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2016 को खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता बीस साल की अवधि से अधिक समय से जेल में

बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई, 2011 को पत्र जारी कर कहा था कि आतंकवादी अपराधों को एक अलग श्रेणी में रखा जाए और सजा कम करने पर विचार से पहले अभियुक्त को कम से कम बीस साल की सजा भुगतनी जरूरी है। याचिका में हा गया कि याचिकाकर्ता बीस साल की अवधि से अधिक समय जेल में भुगत चुके हैं। ऐसे में उन्होंने समय पूर्व रिहाई के लिए गृह मंत्रालय में अध्येवेदन दिया था, लेकिन उसे दिसंबर, 2022 और मार्च, 2024 को खारिज कर दिया गया। ऐसे में गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर उन्हें समय पूर्व रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार के एएसजी भरत व्यास ने कहा कि जिन आरोपियों को टाडा के तहत सजा दी जाती है, उनकी सजा को कम करने पर प्रतिबंध है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

रत्न एवं आभूषण के महाकुंभ “जयपुर ज्वैलरी शो” का आज होगा शुभारंभ

जयपुर (कासं)। रत्न एवं आभूषण के महाकुंभ “जयपुर ज्वैलरी शो” इस वर्ष कलई जेमस्टोन्स थ्री के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 19 से 22 दिसंबर तक होगा। शो का उद्घाटन शुक्रवार प्रातः मुख्य अतिथि एंजीलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, इंक. (जीआईए) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रोतेशा पटेल करेंगे।

जेजेएस मानद सचिव राजीव जैन ने बताया कि जेजेएस वर्ष 2025 में 1227 बूथ्स और 660 एंजीबिटरस के साथ अब तक का सबसे बड़ा और विशाल शो होगा। इन बूथ्स में 624 गोल्ड ज्वैलरी, 314 लूज स्टोन्स, 74 सिल्वर ज्वैलरी की हॉंगी, जबकि 74 एलाइड मशीनरी के बूथ्स होंगे। जेजेएस में इस वर्ष भी ज्वैलरी सैंक्शन में लगभग 66 प्रतिशत डिजाइनर बूथ्स हैं, जो जेजेएस को न केवल खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि विजिटर्स को नयेपन का एहसास होगा। इसके अतिरिक्त, बी2बी ग्राहकों के लिए जेजेएस के मुख्य आकर्षण पिंक क्लब में 74 प्री-फैब्रिकेटेड बूथ्स हैं, जिसमें 44 ज्वैलरी और 30 जेमस्टोन्स के बूथ्स होंगे। वहीं,



डिजाइनरों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए, जयपुर ज्वैलरी शो इस वर्ष 8वें जयपुर ज्वैलरी डिजाइन फेस्टिवल (जेजेडीएफ) की मेजबानी कर रहा है, जिसके अंतर्गत 67 बूथ्स होंगे। जेजेएस वाईस चेयरमैन, दिनेश खटोरिया ने बताया कि केवल 67 बूथों के साथ एक छोटी-सी शुरुआत करने वाला जयपुर ज्वैलरी शो आज अपने 23 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर में नई ऊंचाइयों को छू चुका है। इस वर्ष मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 श्वेता शारदा जयपुर ज्वैलरी शो की ब्रांड एम्बेसेडर हैं। खटोरिया के अनुसार जेजेएस में ना केवल पुराने एंजीबिटरस लगातार जुड़े हुए हैं, बल्कि नए एंजीबिटरस ने भी इस

ब्रान्ड में भाग लेने में गहरी रूचि दिखाई। जेजेएस-2025 में नए एक्जीबिटरस के साथ- साथ ही कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा लेंगे। वहीं, शो में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एंजीबिटरस भी हिस्सा ले रहे हैं। जिसमें बैंकॉक से बूथ होगी। इसके अतिरिक्त, जयपुर सहित मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलूर, हैदराबाद और अहमदाबाद से भी एंजिबिटरस शामिल ले रहे हैं। इस वर्ष 8000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स के शामिल होने की भी उम्मीद है। जेजेएस प्रवक्ता अजय काला ने बताया कि ‘दिसम्बर शो’ के रूप में लोकप्रिय जेजेएस लगभग 50 हजार देशी एवं विदेशी विजिटर्स के साथ देश का एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है।

आरओ-ई.ओ. परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करने वाला बदमाश गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी ग्रेड- और अधिशाषी अधिकारी वर्ग- (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा – 2022 में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये परीक्षा में नकल करने वाले फरार चले रहे दस हजार रुपये के इनामी आरोपित सुरेश कुमार निवासी खाजुवाला जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्व अधिकारी ग्रेड- और अधिशाषी अधिकारी वर्ग- (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा – 2022 के संबंध में अभ्यर्थियों के परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच किए जाने के दौरान तकनीकी वित्तेक्षण से स्पष्ट हुआ कि तुलछाराम कालेर व पाँवर

कालेर गैंग द्वारा परीक्षा के दौरान सालासर में मौजूद रहकर परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये परीक्षा में नकल करवाई है।

इस पर एसओजी ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यक्ष) अधिनियम 2022 में मामला दर्ज जांच पड़ताल की तो सामने आया कि आरोपित सुरेश कुमार इस परीक्षा में अभ्यर्थी था।

जिसने पोरव कालेर गैंग से मिलकर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल की थी। आरोपी सुरेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज होते हुए वह फरार हो गया था। इस पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस प्रकरण में अब तक कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इंजीनियर्स की भूमिका सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं : यूडीएच मंत्री

जयपुर । राजस्थान आवासन मंडल में नव-नियुक्त लगभग 100 से अधिक अभियंताओं को आधुनिक एवं व्यावहारिक अभियांत्रिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन 18-19 दिसम्बर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ गुरुवार प्रातः

- हाऊसिंग बोर्ड में नवनियुक्त 100 इंजीनियर्स के लिए 2 दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन

10 बजे नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खरं ने किया। कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के उपक्रम के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में मंत्री झाबर सिंह खरं ने कहा कि तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य में अभियंताओं की भूमिका



नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खरं ने गुरुवार को आवासन मंडल के नवनियुक्त इंजीनियर्स की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, टिकाऊ, ऊर्जा-दक्ष एवं किफायती आवास की अवधारणाओं को व्यवहार में उतारना होगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियंताओं को नवीन तकनीकों से जोड़ने के साथ-साथ परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक

सिद्ध होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल के माध्यम से विभिन्न आए वर्ग के लिए आवास प्रदान के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग देवाशीष पृथी तथा आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण को

संगठनात्मक क्षमता निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री, नवीन निर्माण तकनीक, लागत प्रभावी समाधान एवं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे अभियंताओं को राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी।

बीकानेर के पीबीएम में कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाया, तबीयत बिगड़ी

पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में मरीज भंवरी देवी को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाया

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में एक मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिया। यहां मरीज भंवरी देवी (75) को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के वक्त कैंसर विंग में एक डॉक्टर और दो नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया। तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई।

परिजनों के अनुसार, भंवरी देवी को खून की कमी के चलते भर्ती किया गया था। उनका ब्लड ग्रुप ए प्लस है। पहले 'ए' पॉजिटिव ब्लड की एक यूनिट चढ़ाई गई। इसके बाद दूसरी यूनिट की जरूरत बताई गई। परिजन ब्लड बैंक से एक और यूनिट लेकर आए, लेकिन वहां से गलत ग्रुप (बी पॉजिटिव) का ब्लड दे दिया गया। कैंसर विंग के नर्सिंग स्टाफ ने बिना

- जब भंवरी देवी को गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा था, तभी वहां मौजूद एक परिजन की नजर ब्लड यूनिट पर लिखे ग्रुप पर पड़ी**

- परिजन ने तुरंत नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को मौके पर बुलाया तुरंत इलाज शुरू किया गया, जिससे महिला की हालत संभल गई**

- कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे, दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था**

- गलत खून चढ़ाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट मांगने पर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई**

क्रॉस चेक किए वही ब्लड मरीज को चढ़ा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।

जानकारी के अनुसार कैंसर विंग में भंवरी देवी नाम की दो महिला मरीज भर्ती थीं, जिनके पति के नाम अलग-अलग थे। दोनों मरीजों को खून चढ़ाया जाना था। नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की पहचान करते समय पति का नाम और अन्य पहचान विवरण नहीं देखे। दूसरी

भंवरी देवी के लिए मंगवाया गया ब्लड पहली भंवरी देवी को चढ़ा दिया। गलत ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होते ही

करीब 30 सेकेंड के भीतर मरीज की हालत बिगड़ने लगी। मरीज को घबराहट और बेचैनी होने लगी। तभी वहां मौजूद परिजन की नजर ब्लड यूनिट और मरीज के ब्लड ग्रुप पर पड़ी। परिजन ने तुरंत डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को मौके पर बुलाया और

ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुकवाया।

घटना की शिकायत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा से की गई। कुछ ही देर में प्रिंसिपल खुद कैंसर विंग में पहुंच गए। कैंसर विंग के एचओडी डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही रात में मौके पर पहुंचे थे। पेशेंट की हालत फिलहाल बिल्कुल स्थिर है। उसका हीमोग्लोबिन 4.4 ग्राम प्रतिशत था, जिस कारण रात में उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ समस्या सामने आई।

डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी विभागों के साथ बैठक कर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर या टेक्नीशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विभागीय और प्रिंसिपल स्तर पर जांच

दुकान का शटर काट 17 लाख की ज्वैलरी ले गए चोर

अलवर, (निसं)। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में 60 फीट रोड के पास रामनगर कॉलोनी कट पर स्थित कृतिका ज्वैलर्स पर अज्ञात चोरों ने रात के सवाते में सेंध लगाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सुबह के समय पड़ोसी दुकानदार की नजर टूटी हुई शटर पर पड़ी, तो उन्होंने फौरन दुकान मालिक को खबर दी और पुलिस को सूचित किया। एनईबी थाने के एसएचओ दिनेश चंद मीणा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में दुकान मालिक ने बताया कि चोर करीब 70 ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। चोरी गए माल की अनुमानित

- पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली**

कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद से ज्वैलर्स सदमे में है।

कृतिका ज्वैलर्स के मालिक बंटी ने बताया कि वह बुधवार शाम दुकान बंद कर सूर्य नगर स्थित अपने घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार के जरिए चोरी की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी कैमरे में चोरों की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है।

अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या

अलवर, (निसं)। अलवर में नौ साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। मर्डर का शक पिता पर ही जताया जा रहा है। पुलिस बच्ची के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का गुरुवार सुबह आठ बजे का है।

एसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 9 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था। बच्ची गुरुवार सुबह 8 बजे घर से बकरियां छोड़ने के लिए जंगल में गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बच्ची के शरीर पर खरोंच के निशान भी है।एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। बच्ची के ताक और ममेरे भाई ने अलग-अलग शिकायत दी है। ममेरे भाई ने बच्ची के पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ताक ने हत्या की आशंका जताई है।

बच्ची के ताक ने बताया कि जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की। अक्सर बच्ची बकरियां छोड़ने के बाद कुछ

- मर्डर का शक पिता पर ही जताया, पुलिस पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था**

ही देर में घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आई तो उसकी तलाश की। इसी दौरान झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना मिली। बच्ची चार बहन-भाइयों में तीसरे नंबर की थी।

प्रारंभिक जांच में बच्ची के गले और शरीर पर खरोंच के निशान मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची की मां पीहर गई हुई थी। पुलिस आफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।

15 साल पुराने हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा शर्मा ने 15 साल पुराने हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी भागीरथ, किशोर उर्फ किशोरसिंह और रामप्रकाश उर्फ गुट्टा को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.56 लाख जुर्माने की सजा दी है।

मामला करीब पंद्रह साल पुराना है। 28 फरवरी 2010 को होली के दिन जोधपुर के पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और कांच की टूटी बोटलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। सरकार की ओर से अपर लोक अधियोजक मयंक रंकावत ने पक्ष रखा।

परिवादी कानाराम ने पीपाड़ शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दफ्तरी रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी 2010 की

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में लोगों को उकसाकर और दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में डीडवाना पुलिस ने लालचंद डेविड नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने 15 से 20 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और खासतौर पर गरीब, पिछड़े व कम शिक्षित वर्ग के लोगों को निशाना बनाया।

मामले को लेकर पुलिस उप अधीक्षक जेदू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डीडवाना निवासी राहुल द्वारा डीडवाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लालचंद डेविड पर लोगों को बहला-फुसलाकर और मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपों की पुष्टि होती चली गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लालचंद डेविड मूल रूप से हिंदू

- पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के खांटा गांव में पालड़ी चौराहे पर शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में दिनेश की चाकू और कांच की टूटी बोटलों से हमला कर हत्या कर दी गई थी**

से जबरदस्ती 3500 रुपए छीनकर बोलेंगे में चले गए।

इसके बाद राजूराम दुकान बंद करके दिनेश, रामकरण, सांवरराम के साथ घर जाने के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वे पालड़ी चौराहे पर आए तभी रामनिवास व उसके साथी बोलेंगे लेकर आड़े फिरें और नीचे उतरकर चारों पर जानलेवा हमला कर दिया। रामनिवास व माधुराम के पास चाकू, रामप्रकाश के पास गुप्ती व भागीरथ के पास चाकू व टूटी हुई बोटल थी। इन लोगों द्वारा किए गए इस हमले से दिनेश के शरीर पर जगह-जगह चाकूओं से गोद दिया। रामकरण के पेट व शरीर पर बोटल व चाकू से जगह-जगह चोटें आईं। राजू



आरोपी लालचंद डेविड

था। करीब आठ वर्ष पहले उसकी माता के बीमार होने के दौरान वह ईसाई पादरियों के संपर्क में आया। उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार

- आरोपी ने 15 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया, लोगों को उकसाकर व दबाव डालकर धर्म परिवर्तन का आरोप**

में सक्रिय हो गया।

जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में लालचंद डेविड डीडवाना पहुंचा, जहां उसने वाल्मीकि समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। वह लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था और प्रभु यीशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था। उसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि कई अन्य लोग धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थे।

यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार

में सक्रिय हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में लालचंद डेविड डीडवाना पहुंचा, जहां उसने वाल्मीकि समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। वह लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था और प्रभु यीशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था। उसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि कई अन्य लोग धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थे।

यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार

में सक्रिय हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि हाल ही में लालचंद डेविड डीडवाना पहुंचा, जहां उसने वाल्मीकि समाज सहित अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू किया। वह लोगों पर हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था और प्रभु यीशु की पूजा करने के लिए प्रेरित करता था। उसके प्रभाव में आकर कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि कई अन्य लोग धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में थे।

यीशु से प्रार्थना की और उसकी माता के स्वस्थ होने के बाद इसे चमत्कार मानते हुए उसने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद से वह ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार

सांवलियाजी सेठ के भंडार से 12.10 करोड़ रुपये निकले



भंडार गिनती में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंडफिया, (निसं)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थस्थल भागवान श्री सांवलियाजी सेठ मंडफिया के दरबार का विशाल भंडार गुरुवार चतुर्दशी को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव व अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में खोला गया।

मंदिर बोर्ड अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि चतुर्दशी को खोले गए भंडार से 12 करोड़ 10 लाख रुपए नगद प्राप्त

- भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी**

हुए। उन्होंने ने बताया कि भंडार से बची राशि की गणना एवं भंडार से निकले सोने-चांदी का तोल होना बाकी है। मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों द्वारा भेंट किए गए सोने-चांदी का तोल एवं

यूआईटी लॉटरी मामले में एईएन को एपीओ किया

भीलवाड़ा, (निसं)। यूआईटी लॉटरी मामले में विवादों में घिरे यूआईटी के सहायक अभियंता (वर्गएन) रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया, हालांकि इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। वहीं लॉटरी के खिलाफ गठित संघर्ष समिति ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है।

नगरीय विकास विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार, भीलवाड़ा में तैनात सहायक अभियंता रविश श्रीवास्तव का तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। प्रशासनिक कारणों से उन्हें अभी कोई नई जिम्मेदारी (पोस्टिंग) नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें जयपुर सचिवालय (हेडक्वार्टर) भेज दिया गया है। जब तक अगला आदेश नहीं आता, उन्हें जयपुर के नगर विकास विभाग में अपनी हाजीरी देनी होगी। श्रीवास्तव यूआईटी की ऑन लाइन लॉटरी में मुख्य सूत्रधार थे और उन्हीं के

द्वारा इस लॉटरी को संपादित करवाया गया था। लॉटरी में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विगत 2 महीनों से भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। भीलवाड़ा की जनता के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद यूआईटी के अधिकारियों ने भी ऑनलाइन प्रक्रिया में टेक्निकल एरर की बात को स्वीकार किया था।

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले में जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सख्त एक्शन नहीं हो पाया। इस संबंध में सरकार के दो साल के जश्न को लेकर भीलवाड़ा आए डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी प्रेमचंद वैरवा के समक्ष संघर्ष समिति के संयोजक विजयपाल सिंह ने दस्तावेजों के साथ कार्यवाही की मांग उठाई, उसके बाद विवादों में घिरे यूआईटी एईएन रविश श्रीवास्तव को एपीओ कर दिया गया।

20 को सीएम के मांडलगढ़ दौरे की तैयारियां तेज

भीलवाड़ा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 20 दिसंबर को प्रस्तावित मांडलगढ़ दौरे को लेकर प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू द्वारा कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल भी साथ मौजूद रहे और तैयारियों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

विधायक खंडेलवाल ने जनसभा में अधिक से अधिक आमजन को सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता महत्वपूर्ण है और इसके लिए व्यापक स्तर पर समन्वय किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था,

- जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू व विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल ने कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया**

यातायात, पार्किंग, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनमोहन शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण जैन सहित संबंधित विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत

- मामले में पुलिस उप निरीक्षक फरार, एसीबी की टीम तलाश कर रही है**

परिवादी को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में बुला कर सागर गहलोत को धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमे पर परिवादी का भी नाम डालकर उसको फंसाते एवं गिरफ्तार करने की धमकी देकर मुकदमे से नाम हटाने की एवज में तीस हजार रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं, जिस पर एसीबी जोधपुर (एसयू) टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबल को भविष्य कुमार को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने परिवादी की गाड़ी में बैठकर बीस हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और वहीं पुलिस उप निरीक्षक प्रेमनाथ एसीबी कार्यवाही की भनक लगने से मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

जैसलमेर, (निसं)। जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सुथार मंडी रोड पर गुरुवार को एक सड़क हादसा हो गया। कृषि उपज मंडी के पास एक तेज रफ्तार निजी बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक को करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गई। इस भयावह मंजर में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस ड्राइवर व कंडक्टर मौके से बस को छोड़कर फरार हो गए। मोहनगढ़ पुलिस ने अनिल विश्रनोई के शव को हॉस्पिटल भिजवाया और बस को जब्त कर ड्राइवर कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, बस मोहनगढ से अनूपगढ की ओर जा रही थी। इसी दौरान सुथार मंडी रोड पर सामने से आ रही बाइक को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान अनिल कुमार विश्नोई (30 वर्ष) पुत्र राकेश कुमार विश्नोई, निवासी ग्राम पंचायत जवाहरनगर, पुलिस थाना पीटीएम के रूप में हुई है।

